(ख) 1981–82 में देश में लगभग 16.00 लाख मी० टन० सीमेंट का आयात किया गया था। सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण योजना लागू हो जाने से सरकार की ओर से सीमेंट का आयात बन्द कर दिया गया है। किन्तु, सीमेंट की पूर्ति में होने वाली कमी को आंशिक रूप से पूरा करने और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सीमेण्ट की आवश्यकता पूरी करने के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से राज्य व्यापार निगम तथा प्रत्येक राज्य सरकार या संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नियुक्त एक सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा सीमेंट का आयात किए जाने की अनुमति है। अतएव, ऐसी अवस्था में यह बता सकना संभव नहीं है कि वर्ष 1982–83 में कितनी मात्रा में सीमेण्ट का आयात किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रत्येक मिनी सीमेण्ट सयंत्र की क्षमता 66,000 मी० टन/प्रति वर्ष तक ही सीमित होने और चूंकि अभी तक केवल कुछ ही मिनी सीमेण्ट संयंत्रों ने उत्पादन शुरू किया है, अत: मिनी सीमेण्ट संयंत्रों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन से देश में सीमेण्ट की समग्र उपलब्धता पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके तथा नई क्षमता के लिए स्वीकृति सीमेण्ट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

Production, Prices and Distribution of Cars

*185. SHRI GHULAM MOHAMMAD KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) the total number of cars produced in the country annually;

(b) the prices of these cars;

(c) whether any specific norms have been decided for distribution of passenger cars and the delivery period of different cars;

(d) the incidence of tax on a car; and

(e) proposals under consideration of Government to reduce the waiting period, lower level of taxation and make available more cars in the country?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (e) A statement is attached.

Statement

(a) The total production of cars in 1981-82 was about 42,500.

(b) The show room prices at Delhi of the principal makes on 16th July, 1982 were:

Ambassador	Rs. 73,525.20
Premier	Rs. 69,604,26

(c) There is no Government control on the distribution of cars which are sold by the manufacturers in accodance with their commercial procedures. The Ambassador vehicle is reported to be readily available. The waiting period for the Premier cars in currently reported to be over 5 years.

(d) There is a 25 per cent Central excise duty on the car pluse a surcharge of 5 per cent over the excise duty. In addition, cars are exigible to a 4 per cent inter-state sales tax and the local sales tax levied by States which may differ from State to State.

(e) As far as the Premier Padmini car manufactured by M/s. Premier Automobiles Limited is concerned, the company has been advised to step up production. Moreover, looking to the overall needs of the country, Government have established Maruti Udyog Limited which would mnufacture passenger cars and the light commercial

versions thereof in the first phase. The production of cars by the company would help reducing the waiting lists.

As regards the lower levels of taxation, a proposal for reduction of duties levied and collected by the Central Government is presently being examined by the Government.

Survey to Locate Atomic Minerals

*186. SHRI SUBHASH YADAV Will the PRIME MINISTER be pleased to lay a statement showing:

(a) whether it is a fact that a survey has been conducted by Government during the last five years to locate mines containing atomic minerals;

(b) if so, the names and the number of such mines located so far; and

(c) how many of them have started functioning and are in production?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (c) Since 1950 the Atomic Minerals Division of the Dept. has been engaged in country-wise surveys to locate Atomic Minerals Deposists. None of the areas located during the last five years have so far reached the mining stage and further detailed sub-surface investigations are being done.

दिल्ली कैंट में सैनिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन

*189. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री उत्तम भाई एच० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली कैंट में एक "जवान" की पत्नी के साथ गुंडों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के विरुद्ध सैनिकों ने बड़े पैमाने पर विरोध में दगा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अभी तक तथाकथित गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और यदि हां, तो उन्हें गिरफ्तार करने लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रहीं है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

24 जून, 1982 की शाम को एक लांसनायक की पत्नी के साथ जब वह सदर बाजार मार्किट में खरीदारी कर रही थी, दुर्व्यवहार की एक घटना हुई । अगले दिन एक घटना जिसमें रक्षा कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति ग्रन्तर्ग्रस्त थे हुई । साइकिलों समेत कुछ दुकानों और दो पहिये वाले कुछेक स्कूटरों को क्षति पहुंचाई गई । तीन रक्षा कार्मिकों और छः पुलिस कार्मिकों को मामूली चोट आई । पुलिस ने एक मामला दर्ज किया । दिल्ली के उपराज्यपाल, केन्द्रीय गृह सचिव और पुलिस आयुक्त लगभग मध्य रात्रि को घटनास्थल पर गये । गृह मंत्री द्वारा अगले दिन बुलाई गई उच्च स्तरीय एक बैठक में घटना की समीक्षा भी की गई जिसके बाद निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) सेना प्राधिकारियों द्वारा कोर्ट आफ इंनक्वायरी का आदेश दिया गया ।

(2) इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई ।

(3) यह क्षेत्र रक्षा कार्मिकों के लिये निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया ।